3 OCT 6 2026.qxd 02-10-2026 19:39 Page 1

गिरावटकी सुनामी

भारतीय शेयर बाजारमें गिरावटकी सुनामी चलनेसे हाहाकार मचा हुआ है। २००१ के बाद लगभग २५ वर्षोंमें लगातार आठवें सप्ताहतक यह गिरावटका सिलसिला है। बम्बई शेयर बाजारका कुल बाजार पूंजीकरण २६ लाख करोड़से अधिक घटा है। आठ सप्ताहमें सेंसेक्स लगभग ६,५९० अंक और निफ्टी लगभग २,१४९ अंक नीचे आ गया। एक अक्तूबरको सेंसेक्स ७१,९०९.७० और निफ्टी २२,४२१.९५ के स्तरपर बन्द हुआ था। बाजारमें व्यापक कमजोरी दिखायी दे रही है। मिडकैप और स्मालकैप शेयरोंमें भी उल्लेखनीय गिरावट हुई है। शेयर बाजारमें गिरावटके अनेक कारण हैं, जिसमें अमेरिकी बाण्ड यील्डमें तेज वृद्धि भी शामिल हैं। दस वर्षीय ट्रेजरी यील्डका लगभग ५.३ प्रतिशततक पहुंचाना विशेष मायने रखता है। ऊंची बाण्ड यील्डसे सुरक्षित डालर आधारित निवेश अपेक्षाकृत आकर्षक हो जाते हैं और उभरते बाजारोंसे पूंजी बाहर जानेका दबाव बढ़ता है। विदेशी निवेशकोंकी लगातार बिकवालीसे बाजारकी धारणा कमजोर हुई है। सितम्बरमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकोंने भारतीय शेयर बाजारसे लगभग ३५,८६१ करोड़ रुपये निकाले हैं। इससे अक्तूबरकी शुरुआतमें भी बिकवाली तेज रह सकती है। अमेरिकी-इसरायल-ईरान संघर्षके कारण तेलकी कीमतोंमें तेज उछाल आया है। होर्मुज स्ट्रेटमें किसी नये तनावसे तेलकी कीमतोंमें तेजी आ सकती है। महंगा कच्चा तेल और विदेशी पूंजीकी निकासीका रुपयेपर दबाव पड़ता है। डालरके मुकाबले रुपयेमें गिरावटसे स्थितियां चिन्ताजनक हो गयी हैं। वैश्विक तरलतामें कमी आनेसे भारत जैसे बाजारपर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताका दुष्प्रभाव शेयर बाजारोंपर पड़ा है। पश्चिम एशियाका संकट कबतक रहेगा, यह अभी अनिश्चित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आठ सप्ताहकी लगातार गिरावट अपने आपमें बाजारके भविष्यकी दिशा तय नहीं करती है। लम्बी गिरावटके बाद भी बाजार कुछ समय और कमजोर रह सकता है। यदि कोई सकारात्मक घटनाक्रम सामने आये तो बाजार तेजीसे सुधर भी सकता है। निवेशकोंके लिए यह दौर घबराकर निर्णय लेनेके बजाय जोखिम प्रबन्धनका है। एक साथ बड़ी राशि लगानेसे बचना चाहिए। कर्ज लेकर शेयर बाजारमें निवेश कदापि नहीं करें। निवेशके पूर्व बाजार विशेषज्ञोंसे अवश्य परामर्श करना उचित रहेगा। बाजारकी गतिपर भी देना होगा।

प्राणघातक ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषणका मानव जीवनपर कितना प्रतिकूल और घातक प्रभाव पड़ता है, इसे उत्तर प्रदेशके बलरामपुरमें स्कूलके पास तेज आवाजमें डीजे और लाउडस्पीकर बजनेके दौरान कक्षा दोकी छात्राके कक्षामें गिरने और बादमें उसकी मृत्युकी घटनाके सन्दर्भमें देखनेकी जरूरत है। यह तो अच्छा हुआ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालयकी लखनऊ खण्डपीठने स्वत: संज्ञान लेते हुए ध्वनि प्रदूषणकी बढ़ती समस्या और जुड़े कानूनी प्रावधानोंके पालनकी स्थितिकी जांचके लिए जनहित याचिका दर्ज करनेका निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकारके अधिवक्ताको बलरामपुरके जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकसे इस सम्बन्धमें रिपोर्ट प्राप्त करनेका भी निर्देश दिया है। घटना विगत २२ सितम्बरकी है जब स्कूलके पास जुलूसके दौरान बज रहे डीजे म्युजिक सिस्टम और लाउडस्पीकरकी तेज आवाजसे छात्रा अचानक कक्षामें ही गिर गयी थी। छात्राको तत्काल उपचारके लिए ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ध्वनि प्रदूषणसे सम्बन्धित एक जनहित याचिकापर सुनवाईके दौरान न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति संजीव शुक्लकी पीठने मासूम छात्राकी मृत्युके मामलेको गम्भीरतासे लिया। हालांकि न्यायालयने छात्राकी मौतका कारण तेज आवाज या डीजेको नहीं माना है लेकिन इस बातसे इनकार भी नहीं किया कि घटनाके समय तेज आवाजमें संगीत बजाया जा रहा था और उसके बाद तत्काल छात्रा कक्षामें गिर गयी। यह ध्वनि प्रदूषणके व्यापक मुद्देपर अलगसे स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका दर्ज करनेके लिए पर्याप्त है। वैसे तो प्रदूषण हर हालमें पृथ्वीके जीवधारियोंके लिए घातक है, चाहे वह वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण अथवा ध्वनि प्रदूषण। इसे रोकनेके उपाय होने चाहिए। इसके लिए योजनाएं भी संचालित हैं और कानूनी प्रावधान भी बनाये गये हैं लेकिन इसका कितना अनुपालन होता इसे भी देखा जाना चाहिए। जहांतक ध्वनि प्रदूषणका सवाल है तो शादी-विवाह समारोह, जुलूसमें तेज आवाजमें डीजे बजाना चलन बन गया है, बिना साइलेंसरके तेज रफ्तारमें सड़कोंपर बाइक दौड़ाना युवाओंका शौक बनता जा रहा है लेकिन इनपर जिला प्रशासनकी निगाह नहीं पड़ती। ध्वनिके लिए एक मानक तय किया जाना जरूरी है और इसका अनुपालन कड़ाईसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लोक संवाद

कामयाबीका रास्ता

महोदय,-१८९० के दशकमें किंग सी. जीलेट नामक एक व्यक्ति एक बोतलके ढक्कन बनाने वाली कम्पनीमें सेल्समैनका काम करते थे। एक दिन उनके मालिक विलियम पेंटर बोले, किंग, तुम अधिकतर नयी-नयी चीजोंके बारेमें सोचते रहते हो। कुछ ऐसा सोचो न कि तुम्हारा नाम पूरी दुनियामें हो जाय। मालिककी बात जीलेटके मन-मस्तिष्कमें बस गयी। एक दिन वे अपने पुराने उस्तरेसे शेव बना रहे थे। उस्तरा भोथरा था। उसे बार-बार चमड़ेपर रगड़कर धार बनानी पड़ रही थी। तब उनके दिमागमें विचार आया कि शेव बनानेके लिए ऐसा कोई पतला और छोटा-सा उपकरण नहीं बन सकता, जिसे प्रयोग करके फेंक दिया जाय। वे अपने इस विचारको लेकर धातुकर्म विशेषज्ञोंके पास गये। उन्होंने उनके विचारका मजाक उड़ाया और कहा कि इतनी पतली, सस्ती और धारदार स्टील ब्लेड बनाना असंभव है, जिसे प्रयोग करके फेंक दिया जाय। जीलेटने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथ विलियम निकरसन नामक वैज्ञानिकको लिया और काममें लग गये। वे कई बार असफल रहे, परन्तु आखिर उन्होंने डिस्पोजेबल सेफ्टी रेजरका आविष्कार कर दिया। कुछ ही समयमें उनके द्वारा बनाये गये ब्लेडोंकी पूरे विश्वमें धूम मच गयी और किंग सी. जीलेट प्रसिद्ध हो गये। **-रेणु सैनी, वाया ईमेल।**

वैश्विक पूंजी युद्धके लिए तैयार रहे भारत

वैश्वीकरणसे पीछे हटती दुनियामें सीमाओंके पार लोगोंकी आवाजाहीपर पहले ही कई तरहके प्रतिबंध दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्पकी अमेरिकाके राष्ट्रपति पदपर वापसी और नीतिगत दबावके औजारके रूपमें टैरिफके इस्तेमालके बाद वैश्विक स्तरपर वस्तुओं और सेवाओंके व्यापारको भी झटका लगना तय है।

❐ टी.एन. निनाद

वैश्वीकरणके बाद अमीर देशोंकी ओरसे पूंजीकी अंतरराष्ट्रीय आवाजाहीपर प्रतिबंधोंके बाद विकासशील देशोंमें पूंजी नियंत्रण लम्बे समयसे सामान्य बात रही है। इस तरहके बड़े बदलावकी प्राथमिक वजह अमेरिकामें दिखाई दे रही है, जहां कम्पनियोंकी बढ़ती कर्ज जरूरत और अमेरिकाके बजट घाटेके बीच टकराव बढ़ रहा है। तकनीक और कृत्रिम मेधा (एआई) की दौड़में आगे चल रही बड़ी कम्पनियां कुछ समय पहलेतक अपने पूंजीगत खर्चकी जरूरतें अपनी कमाईसे पूरी कर रही थीं। अब ऐसा नहीं है। निवेश योजनाओंमें भारी विस्तारके कारण ये कम्पनियां बाजारसे बड़ी मात्रामें कर्ज उठा रही हैं। अमेरिकामें कारपोरेट बाण्ड जारी किये जानेकी मात्रा दो वर्षोंमें ८० प्रतिशत बढ़ गयी है। दूसरी ओर संघीय बजट घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के सात प्रतिशततक पहुंच गया है और इसके जल्द नियंत्रित होनेके कोई संकेत नहीं दिख रहे। अमेरिकाकी घरेलू बचत इन बढ़ती पूंजी जरूरतोंको पूरा करनेके लिए पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका दशकोंसे दुनियाका सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बना हुआ है। लेकिन विदेशोंसे पूंजीकी उसकी बढ़ती जरूरत ऐसे समयमें सामने आ रही है, जब लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकी प्रतिभूतियोंसे दूरी बना रही हैं।



यदि सरकारों तथा कम्पनियोंकी कर्ज लेनेकी होड़ जारी रहती है तो पूंजीके लिए अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। इससे महंगी बढ़ेगी या देशोंके बीच पूंजीके प्रवाहपर प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। इसलिए भारतके लिए विदेशी मुद्रा भंडारको मजबूत करना, बजट घाटे और सरकारी कर्जको कम करके आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना तथा देशको निवेशकोंके लिए अधिक आकर्षक बनाना महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडारका इस्तेमाल रुपयेमें अस्थिरतासे निबटने और जरूरत पड़नेपर पूंजीके बाहर जानेकी स्थितिमें किया जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्थाकी बाहरी भुगतान क्षमताको लेकर भरोसा बढ़ेगा।

चीनने पिछले कुछ वर्षोंमें अमेरिकी प्रतिभूतियोंमें अपनी हिस्सेदारी आधी कर दी है, जबकि अब अमेरिकी प्रतिभूतियोंका सबसे बड़ा धारक जापान भी इससे दूरी बनाना शुरू कर चुका है। बाजारमें कारोबार योग्य अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियोंमें विदेशी निवेशकोंकी हिस्सेदारी २०१५ में ५० प्रतिशत थी, जो अब घटकर ३० प्रतिशत रह गयी है। केन्द्रीय बैंक जहां अपने डालर भण्डारमें कटौती कर रहे हैं, वहीं उन्होंने अपने विदेशी मुद्रा भंडारमें सोनेकी हिस्सेदारी बढ़ायी है। पिछले साल सोनेने अमेरिकी सरकारी बाण्डको पीछे छोड़ते हुए केन्द्रीय बैंकोंकी रिजर्व परिसंपत्तियोंमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली। एक सालमें सोनेकी कीमत २५ प्रतिशत बढ़ चुकी है और भारतीय अब भी सोनेके बड़े खरीदारोंमें शामिल हैं।

अमेरिकी डालरमें बढ़ते कर्ज और इस कर्जको लेकर घटती वैश्विक मांगके बीच इसका स्वाभाविक असर ब्याज दरोंपर पड़ा है। अमेरिकी ट्रेजरीकी ब्याज दरें अब दो दशकोंके उच्चतम स्तरपर हैं और लगातार बढ़ रही हैं। इसके बावजूद नये अमेरिकी कर्जकी नीलामीमें अंतरराष्ट्रीय खरीदारोंकी हिस्सेदारी पहलेके मुकाबले कम हो गयी है। पांच सालकी ट्रेजरी प्रतिभूतियोंपर ब्याज दर महज एक महीनेमें ०.६४ प्रतिशत बढ़ गयी है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट पिछले कुछ सप्ताहसे बाजारको शांत करनेके लिए कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हुआ है। यदि ऊंची ब्याज दरोंके बावजूद अमेरिकाको दूसरे देशोंसे अपनी जरूरतके मुताबिक पूंजी नहीं मिलती है तो वह डालरकी आपूर्ति बढ़ा सकता है। इससे बाजारमें अधिक पैसा आनेके कारण महंगी बढ़ सकती है और वास्तविक यानी महंगी-समायोजित अर्थोंमें उसके कर्जका बोझ कम हो सकता है। भारत दशकोंसे ऐसा करता रहा है। वास्तवमें पश्चिमी देशोंका कर्ज बढ़नेके साथ पिछले पांच वर्षोंमें अमेरिकामें महंगी पिछले दशककी तुलनामें दोगुनेसे अधिक, यूरोपमें तीन गुना और जापानमें पांच गुना अधिक रही है। इसे कर्जके बोझको नियंत्रित करनेके लिए छेड़े गये महंगी युद्धके रूपमें देखा जा सकता है। एक और संभावना है, हालांकि अभी यह दूरकी बात लगती है, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं है कि अमेरिका व्यापारकी तरह पूंजीके मामलेमें भी दबावकी नीति अपना सकता है। ट्रम्प पहले ही कुछ द्विपक्षीय व्यापार समझौतोंमें निवेश प्रतिबद्धताओंको शामिल कर चुके हैं। आज वह पूंजीके प्रवाहको अमेरिकामें आनेके लिए मजबूर कर रहे हैं, कल पूंजीके बाहर जानेपर भी अंकुश लगाया जा सकता है।

इस आशंकाको देखते हुए कुछ देशोंने रक्षात्मक कदम उठाने शुरू कर दिये हैं। नीदरलैंडने पिछले कुछ महीनोंमें न्यूयॉर्कसे ७८ टन सोना लंदन स्थानांतरित किया है। इसके पीछे संभावित भूराजनीतिक अस्थिरताको कारण बताया गया। इससे कुछ समय पहले फ्रांसने भी अमेरिकामें रखा अपना पूरा सोना वापस निकाल लिया था। जर्मनीमें भी ऐसा ही करनेकी मांग उठ रही है। कुछ समय पहलेतक जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, अब अमेरिकी पूंजी बाजारके लगातार खुले रहनेको लेकर भरोसेमें मामूली ही सही, लेकिन कमी आने लगी है। इसी बीच यूरोपके विशेषज्ञोंने यूरोपीय पूंजीके अमेरिका जानेको हतोत्साहित करनेकी वकालत की है, क्योंकि यूरोपको अपने भीतर निवेश करनेकी जरूरत है। यूरोपकी ओरसे ऐसा कोई भी कदम उठाये जानेपर वाशिंगटनकी ओरसे जवाबी कारवाईकी संभावना लगभग तय मानी जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्समें सितंबरकी शुरुआतमें प्रकाशित एक शीर्षक 'पूंजी युद्ध आ रहे हैं' इस बदलते माहौलको रेखांकित करता है। इन घटनाक्रमोंसे भारतको गम्भीर चिन्ता होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षोंसे पोर्टफोलियो पूंजी भारतसे बाहर जा रही है और रुपयेके मूल्यमें १३ प्रतिशतकी गिरावट आयी है। यह गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सक्रिय हस्तक्षेपके बावजूद हुई है। इस बीच बढ़ती ऊर्जा कीमतोंने व्यापार संतुलनपर भी दबाव डाला है। प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक भी उस स्तरपर लौट आये हैं, जहां वे करीब ढाई साल पहले थे। पिछली बार शेयर बाजारने इतने लम्बे समयतक निवेशकोंको निराश २००८ के वैश्विक वित्तीय संकटके बाद किया था। इन परिस्थितियोंमें आरबीआईकी सबसे बड़ी पहल अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आकर्षक ब्याज दर और मुद्रा सुरक्षाके साथ जमा योजनाकी पेशकश करना रही। हालांकि संभव है कि केन्द्रीय बैंकने इस मामलेमें कुछ ज्यादा ही उदार रुख अपनाया हो। योजनासे अनुमान से दोगुनी राशि १३० अरब डालरसे अधिक जमा हुई। एनआरआई जाहिर तौरपर ऐसे मुफ्तके फायदेको पहचानना जानते हैं। इस योजनाकी आरबीआईपर लागत मुद्रा विनिमय दरमें होने वाले बदलावपर निर्भर करेगी और पूरी योजनाकी अवधिमें यह १० से २० अरब डालरके बीच हो सकती है।

इस योजनाके आलोचकोंने मुख्य रूपसे दो तर्क दिये हैं। पहला, भारतकी विदेशी मुद्रा भंडार स्थिति आरामदायक है, जबकि अतीतमें एनआरआईको आकर्षक जमा योजनाओंकी पेशकश तब की गयी थी जब विदेशी मुद्रा भंडारकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। उस समय मिलेनियम बाण्ड और रीसर्जेंट इंडिया बाण्ड जैसी योजनाएं लायी गयी थीं। दूसरा तर्क यह है कि इस बार पेश किये गये नियम जरूरतसे ज्यादा उदार थे। इनमें दूसरा तर्क अधिक ठोस नजर आता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारमें अनिश्चितता और तनावको देखते हुए किसी तरहके अहतियाती कदमकी जरूरत थी। फरवरीके अंतसे अगस्तके अंततकके छह महीनोंमें, जब अमेरिकाने ईरानपर हमला किया था, आरबीआईका विदेशी मुद्रा भण्डार ५० अरब डालरसे कुछ अधिक बढ़ा। इस अवधिमें एफसीएनआर(बी) फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (बैंक) जमाके रूपमें करीब १३० अरब डालर आये। न तो चालू खातेका घाटा और न ही शुद्ध पूंजी प्रवाह इस अंतरकी पूरी तरह व्याख्या कर सकता है। जाहिर है कि आरबीआईने पूंजीके देशसे बाहर जानेके कारण रुपयेको संभालनेमें बड़ी मात्रामें डालर खर्च किये हैं। ऐसेमें अतिरिक्त डालर हासिल करना किसी नुकसानका सौदा नहीं है। अब दो संभावनाएं बनती हैं। यदि एआईमें निवेशका बुलबुला फूटता है तो वैश्विक स्तरपर भारी उथल-पुथल हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी शेयर बाजारका हिस्सा वैश्विक बाजार पूंजीकरणमें दो-तिहाईसे अधिक है। दूसरी ओर यदि ऐसा नहीं होता और सरकारों तथा कम्पनियोंकी कर्ज लेनेकी होड़ जारी रहती है तो पूंजीके लिए अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। इससे महंगी बढ़ सकती है या देशोंके बीच पूंजीके प्रवाहपर प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। इसलिए भारतके लिए विदेशी मुद्रा भंडारको मजबूत करना, बजट घाटे और सरकारी कर्जको कम करके आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना तथा देशको निवेशकोंके लिए अधिक आकर्षक बनाना महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडारका इस्तेमाल रुपयेमें अस्थिरतासे निबटने और जरूरत पड़नेपर पूंजीके बाहर जानेकी स्थितिमें किया जा सकता है। इससे उस समय अर्थव्यवस्थाकी बाहरी भुगतान क्षमताको लेकर भरोसा भी बढ़ेगा, जब यह स्पष्ट नहीं है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां किस दिशामें जायंगी।

पानीके लिए बंगलादेशकी कूटनीति

भारतीय मानते हैं कि १९७१ में भारतने जो कुर्बानी दी थी, बंगलादेशने उसके लिए आभार नहीं जताया। इस बातसे इनकार नहीं है कि भारतमें चार पार्टियोंवाली समावेशी सरकारके समय दोनों देशोंके रिश्ते बहुत निचले स्तरपर थे।

❐ पुष्परंजन

जिस शेख हसीनाने फिश डिप्लोमेसीकी शुरुआतकी थी, वह अब राजनीतिके जलसे बाहर हैं। हिलसा बंगलादेशकी राष्ट्रीय मछली है। स्थानीय लोग इसे इलिश कहते हैं। स्वादमें बेजोड़ होनेकी वजहसे इसे मछलियोंकी रानी भी माना जाता है। इलिशके बिना 'एई पार बंगला या ओई पार बंगला' की जनता रह नहीं सकती। बीते २६ सितंबर २०२६ को दिल्ली स्थित बंगलादेश हाई कमीशनमें हिलसा फेस्टिवल आयोजित हुआ था, जिसमें कुछ वरिष्ठ राजनेता, राजनयिक, पत्रकार, शिक्षाविद् और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हुईं। उस हिलसा फेस्टिवलमें तबेपर हिलसा फ्राईका मेहमानोंने लुत्फ उठाया। चाणक्यपुरी स्थित दूतावासके मैत्री ऑडिटोरियममें आयोजित इस उत्सवका मुख्य उद्देश्य फूड एवं कलिनरी डिप्लोमेसीके जरिये भारत और बंगलादेशके बीच सांस्कृतिक संबंधोंको प्रगाढ़ करना था। इस अवसरपर ढाकासे प्रकाशित एक विशेष पुस्तक 'ए फिश कॉल्ड इलिश' का विमोचन भी भारतीय हस्तियों द्वारा किया गया। उत्सवमें आये मेहमानोंको हिलसा मछलीसे बने विभिन्न प्रकारके पारम्परिक बंगाली व्यंजन, जैसे सरसों हिलसा, फ्राइड हिलसा आदिके साथ-साथ पारम्परिक बंगलादेशी भोजन परोसा गया। बंगलादेशके उच्चायुक्त एम. रियाज हामिदुल्लाहने इस अवसरपर कहा कि हिलसा सिर्फ एक मछली नहीं है, बल्कि यह बंगलादेशकी पहचान, समाज और अर्थव्यवस्थासे गहराईसे जुड़ी हुई है। यह आयोजन ऐसे समयमें किया गयाए जब दोनों देशोंके बीच हिलसाके व्यापारिक समीकरणोंको लेकर कई कूटनीतिक चर्चाएं चल रही हैं।

वर्ष १९९१ के बादसे बंगलादेश और भारतके बीच संबंधोंमें उतार-चढ़ाव इन दोनों देशोंके राजनेताओंके सत्तामें आने-जानेके साथ बदलते रहे हैं। शायद किसीको याद हो कि १९ मार्च १९९८ को बीजेपी के दोबारा सत्तामें आनेके बाद बंगलादेशके तत्कालीन विदेशमंत्री आनन-फाननमें नयी दिल्ली पहुंचे थे। यह भूलकर कि पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देशका स्थायी हित महत्वपूर्ण है। उन दिनों शेख हसीना सत्तामें थीं। १६ मईसे १ जून १९९६ तक अटल बिहारी वाजपेयीकी १६ दिनोंकी पहली टर्म वाली सरकारको उन्होंने हल्केमें लिया था। भारतमें कई लोग ऐसा मानते हैं कि १९७१ में भारतने जो कुर्बानी दी थी, बंगलादेशने उसके लिए पर्याप्त आभार नहीं जताया। शायद ही कोई इस बातसे इनकार करेगा कि भारतमें चार पार्टियों वाली समावेशी सरकारके समय दोनों देशोंके रिश्ते बहुत निचले स्तरपर थे। उस दौरान विदेश मंत्री स्तरकी किसी द्विपक्षीय यात्राकी बात तो दूर, सरकार प्रमुखकी यात्रातक नहीं हुई थी। केन्द्रमें सत्ता मजबूत होती है तो रिश्ते भी बदलते हैं। शेख हसीना, 'जैसी बही बयार, पीठ तब तैसी कीजिए', वाली राजनेता रही हैं। दक्षिण एशियामें 'हिलसा डिप्लोमेसी' की शुरुआत १९९६ में सद्भावना और सहयोगके इरादेसे हुई थी। बंगलादेशकी पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीनाने १९९६ की ऐतिहासिक गंगा जल बंटवारा संधिसे ठीक पहले, सद्भावनाके एक सोचे-समझे कदमके तौरपर पश्चिम बंगालके मुख्य मंत्री ज्योति बसुको हिलसा मछलीकी एक खेप भेजी थी।

१२ दिसंबर १९९६ को तत्कालीन प्रधान मंत्री शेख हसीना और उनके भारतीय समकक्ष एच. डी. देवेगौड़ाके बीच हुई ३० सालकी इस संधिने जनवरी-मईके सूखे मौसमके दौरान गंगाके पानीके बंटवारेका एक ढांचा तैयार किया था। इस दौरान नदीका बहाव काफी कम हो जाता है। भारत और बंगलादेशके बीच १९९६ में हुई गंगा जल संधि ११ दिसंबर २०२६ को समाप्त हो रही है। वर्ष १९९६ के बाद उभयपक्षीय परिस्थितियां काफी बदली हैं। आबादी बढ़ी है, पानीकी जरूरत बढ़ी है और नदी तथा मौसमसे जुड़ी परिस्थितियोंको लेकर भी नयी चुनौतियां सामने आयी हैं। नयी संधि होती है तो भारत और बंगलादेशकी जरूरतोंके साथ-साथ भारतके अन्दर अलग-अलग राज्योंकी पानीसे जुड़ी जरूरतोंको भी ध्यानमें रखना होगा। गंगा नदी बंगलादेशके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देशका लगभग ३७ प्रतिशत भू-भाग, जो चार डिवीजनोंके २६ जिलों और १६३ उप-जिलोंमें फैला है, इस नदीपर निर्भर है, जिसे बंगलादेशमें 'पद्मा' के नामसे जाना जाता है। अब आने वाले दशकोंके लिए ढाका और नयी दिल्लीको एक नयी व्यवस्था तैयार करनी होगी।

तीस्ता जल बंटवारेमें हुई उठा-पटककी कहानी अलग है। तीस्ता नदीके लिए पानीके बंटवारेकी एक अलग व्यवस्थाको २०११ में बंगलादेश और भारतने अंतिम रूप दिया था, लेकिन पश्चिम बंगालकी तत्कालीन मुख्य मंत्री ममता बनर्जीके विरोधके बाद उसपर कभी हस्ताक्षर नहीं हो सके। पद संभालनेके बाद मुहम्मद यूनुसकी अंतरिम सरकारने शुरूमें भारतको हिलसाका एक्सपोर्ट रोक दिया था। हालांकि बादमें यह फैसला बदल दिया गया और २१ सितंबर २०२४ को वाणिज्य मंत्रालयने भारतको ३००० टन हिलसा एक्सपोर्ट करनेकी मंजूरी दे दी। २०२५ में २४२० टन हिलसा भारत निर्यात करनेकी मंजूरी दी गयी थी। २०२६ में इसे आधा घटाकर १२०० टन कर दिया गया है। हिलसाके कम-ज्यादा एक्सपोर्टसे ढाका-नयी दिल्लीके बनते-बिगड़ते कूटनीतिक संबंधोंको हम नाप सकते हैं।

नयी सरकारके गठनके बाद भी बंगलादेश चैनसे नहीं है। ऐन दुर्गा पूजाके समय भारत निर्यात होने वाली हिलसा मछली मुद्दा बनती है। हालांकि बंगाली आबादी हिलसाको अपनी खान-पानकी संस्कृतिका अहम हिस्सा मानती है, लेकिन बंगलादेशमें इसे लेकर चिन्ताएं भी हैं। हर साल दुर्गा पूजासे पहले स्थानीय बाजारमें हिलसाकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे मध्यम और निचले वर्गपर और ज्यादा बोझ पड़ता है। कई कॉमन लोगोंके लिए हिलसा मछलीका एक्सपोर्ट अभिशाप भी बन गया है। ममता बनर्जीने चुनावके दिनोंमें कहा था कि बीजेपी सरकार आयी तो मछली-मांसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अब लोग कहने लगे, 'बंगलादेशने फेस्टिव सीजनमें धोखा दिया है।' हिलसाका स्वाद बंगालमें बीजेपीकी सरकारके रहते सर्वसुलभ न हो तो यह राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। रणनीतिकार हिलसाको कूटनीतिक हथियारके तौरपर इस्तेमाल करनेसे बाज नहीं आ रहे। हाई कमीशन द्वारा हिलसा फेस्टिवलके कूटनीतिक मायने नयी दिल्ली समझे। 'आप हमें पानी दो-हम आपको हिलसा देंगे।'



श्राद्ध और श्रद्धा

❐ धर्मेश कुशवाहा

संसार अर्थात् प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील है, जिसमें निरन्तर परिवर्तन रूप क्रिया होती रहती है, उसका नाम प्रकृति है ग्रंथोंमें वर्णित है। प्रकर्षेण करणं प्रकृति:। इसलिए संसार तथा उसका अंश शरीर निरन्तर बदलने वाले हैं। इस परिवर्तनशील प्रकृतिमें जब मनुष्यके शरीरसे प्राण अलग होता है तो वह एक संस्कृत का शब्द प्रेत, जिसका अर्थ है प्रइत यानी शरीरसे बाहर निकलना या दिवंगत होना, हो जाता है इससे यही समझमें आता है कि जब मनुष्यके शरीरसे प्राण निकलता है तो प्रेत हो जाता है। प्रेतसे पितृकी तरफ अग्रसर होनेके लिए ग्यारहवें और बारहवें दिन वंशजोंके द्वारा पिंडदान किया जाता जिससे वहीं प्राण पितृमें जाता है और अपने कर्मों अनुसार भोग भोगनेके बाद दूसरे जन्मकी तरफ कर्मानुसार जन्म लेता है। यदि प्राण पितृकी तरफ नहीं जाता है तो इसी लोकमें अपनी अधूरी तृष्णा लेकर भटकता रहता है। इसलिए वर्षमें एक बार पितरोंके लिए पितृपक्षका १६ दिनोंका समय होता है जिसमें पितरोंको तर्पण आदिका कार्य किया जाता है जिससे पूर्वज प्रसन्न होते है और उनको तृप्ति होती है। अब बात आती है कि जिसका मरनेके बाद कोई कर्मकांड न हो तो वह पितृकी तरफ नहीं जायगा वेदांत और कर्मका सिद्धांत सुना है कि अपने जन्ममें ही इतनी ऊर्जा अपने अच्छे कर्मों द्वारा एकत्रित कर लेनेसे स्वयं ही पितृकी तरफ मनुष्य चला जाता है। संत इसके उदाहरण है। महाभारतमें देवव्रतने आजीवन कुंवारा रहनेका प्रण किया और कहे कि हम अपने कर्मोंसे इतनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे कि किसीकी पितृकी तरफ भेजनेकी जरूरत नहीं होगी स्वयं चले जायंगे और यही हुआ। प्रेतको पितृमें मिलनको ही श्राद्ध कहते है। प्रेत एक अलग है और पितृ एक अलग वातावरण है। श्रद्धासे श्राद्ध बना है। श्रद्धापूर्वक किये गये कार्यको ही श्राद्ध कहते है। श्राद्धसे श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धाको प्रकट करनेका जो प्रदर्शन होता है, वह श्राद्ध कहलाता है। जीवित बुजुर्गों और गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा प्रकट करनेके लिए उनकी अनेक प्रकारसे सेवा पूजा तथा संतुष्टि की जा सकती है। परंतु पितरोंके लिए श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करनेवालेको कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्राद्ध। अपने दिवंगत पूर्वजोंके प्रति श्रद्धा प्रकट करने तथा उनके स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त करनेका यह सर्वोत्तम अवसर है। हिंदु परंपराके अनुसार श्राद्ध पक्षको दिवंगत आत्माओंसे आशीष लेनेका महापर्वके रूपमें भी माना गया है। इसलिए श्राद्धमें श्रद्धा जरूरी है।

सवालोंके घेरेमें चुनाव आयोगकी विश्वसनीयता

❐ रोहित माहेश्वरी

भारतके चुनाव आयोगको अपने मुख्य चुनाव आयुक्तके खिलाफ अनियमितताओंके नये आरोपोंकी एक श्रृंखलाके बाद विश्वसनीयताके एक और संकटका सामना करना पड़ रहा है। विश्वके सबसे बड़े लोकतंत्रमें सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक संस्थानोंमेंसे एक, तीन सदस्यीय आयोगकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं और इसमें सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आयुक्तके रूपमें शामिल हैं। यह ताजा विवाद इंडियन एक्सप्रेस अखबारमें छपी एक रिपोर्टके बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले कुछ महीनोंमें, मुख्य चुनाव आयुक्त कुमारसे उनके दो सहयोगियोंने वोटर डेटाबेसकी सत्यनिष्ठा, नये मतदाताओंके नामांकनके तरीकेमें बदलाव और मतदाता सूचीकी सुरक्षाको लेकर बार-बार सवाल किये हैं।पिछले कुछ वर्षोंमें चुनाव आयोगकी विश्वसनीयताको लेकर देशका विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। ताजा खुलासोंने विपक्षी दलों और आलोचकोंको भी नया बल प्रदान किया है, जो बार-बार दावा करते रहे हैं कि एसआईआरका इस्तेमाल भाजपाके लाभके लिए उनके वोटरोंको बाहर करनेके लिए किया जा रहा है और भारतमें चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहे हैं। हालांकि चुनाव हारनेपर विपक्ष द्वारा चुनाव आयोगपर आरोप-प्रत्यारोप लगानेका सिलसिला पुराना है। लेकिन पिछले कुछ सालोंमें भारतका चुनाव आयोग विश्वसनीयताकी कसौटीपर खरा नहीं उतर पा रहा है। जिसकी तपिश भारतीय लोकतंत्रकी साखपर भी पड़ती है।

निस्संदेह, चुनाव आयोगका दायित्व लोकतंत्रमें पारदर्शी चुनाव कराना और नागरिकोंके वोट देनेके महत्वपूर्ण अधिकारकी रक्षा करना होता है। लेकिन पिछले कुछ समयसे इस संवैधानिक संस्थाकी विश्वसनीयताको विवादित स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआरसे जुड़ी विसंगतियोंने भारी ठेस पहुंचायी है। हालमें दिल्लीके